Sl. No.	State/UT	VIII Plan Alloca-tion	Release of funds (1992-94)
2	Chandigarh	1.00	0.25
3	Dadara & Nagar Haveli	1.00	0.2
4	Delhi	17.50	2.00
5	Daman & Diu	1.00	0.25
6	Lakshadweep	2.00	0.25
7	Pondichery	3.00	1.00
	Total	860.51	234.09

Expenditure on Diet and Medical care in Navodaya Vidyalayas

*253. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) what is the per capita expenditure on students in Navodaya Vidyalayas qn diet and medical care ; and

(b) whether Government are aware that poor quality of food is provided to students in Navodaya Vidyalayas, and if so, what steps are proposed to be taken to ensure good quality of food for the students ?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH) : (a) The per capita expenditure is Rs. 350 per month psr student and on medicines and other miscellaneous expenses is Rs. 60.00 per student per year when schools are open.

(b) Navodaya Vidyalaya Samiti has informed that all efforts are made lo provide pood quality food to the children. Some of the major steps taken by Navodaya Vidyalaya Samiti for imnroving the quality of food are—creation of posts of catering ass:s!ants, surprise visits by Senior Officials. Association of two boys and two !»ir)s in the Mess Committee of each Vidyalaya.

गन्ने का भारी मात्रा में उत्पादन

*254. श्री आस मोहम्मद :

श्री ईश दत्त यादव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान गन्ने का भारी उत्पादन हुआ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में किन-किन राज्यों ने गन्ने का अधिकतम उत्पादन किया;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान इन राज्यों में राज्यवार गन्ने की अधिकतम और न्यूनतम कीमतें क्या थीं:

(घ) क्या चीनी मिलों ने गन्ने के कुल उत्पादन का पूर्ण उपयोग किया है;

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है और चीनी मिलों द्वारा उपयोग में लाए गए गन्ने और बरबाद हुए गन्ने की मात्रा का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(च) गन्ने के सम्पूर्ण उत्पादन के उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है;

(छ) 1994-95 के दौरान गन्ने के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और गत वर्ष की तुलना में इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ज) गन्ने की खेती हेतु राज्यों को क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान गन्ने का उत्पादन इस प्रकार रहा :—

1991-92	: 254.0 मिलियन मीटर टन
1992-93	: 230.8 मिलियन मीटरी टन
1993-94	: 233.0 मिलियन मीटरी टन (अनन्तिम)

(ख) गन्ना उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र तमिल नाडु, और उत्तर प्रदेश है ।

(ग) उपरोक्त पैराग्राफ (ख) में उल्लिखित राज्यों में 1991-92 से 1993-94 की अवधि के दौरान भुगतान किए गए गन्ने के मूल्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है **(नीचे देखिए)** ।

(घ) और (ङ) गन्ने के कुल उत्पादन को चीनी मिलों द्वारा अथवा गुड़ या खाण्डसारी इकाइयों द्वारा पूर्णतया उपयोग कर लिया गया है । गन्ने के नष्ट होने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है । चीनी के निर्माण के लिए उपयोग किए गए गन्ने की अनुमानित प्रतिशतता 1991-92 में 52.8 प्रतिशत, 1992-93 में 44.6 प्रतिशत और 1993-94 में 42.0 प्रतिशत आंकी गई है ।

(च) सरकार और अधिक चीनी मिलों की स्थापना करने और विद्यमान चीनी मिलों की क्षमता को बढ़ाने तथा उनका नवीकरण करने के लिए स्वीकृति दे रही है ताकि गन्ने के उत्पादन को पूर्णतया उपयोग करने के लिए चीनी मिलों की समग्र क्षमता में सुधार किया जा सके । सरकार चीनी मिलों द्वारा 1 अक्तूबर से 15 नवम्बर तक गन्ने की शीघ्र पेराई और मई तथा जून में देर से पेराई के लिए भी प्रोत्साहन दे रही है ।

(छ) 1994-95 के दौरान गन्ने के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य 250 मिलियन मीटरी टन है। 1994-95 में गन्ने के उत्पादन में गत वर्ष के उत्पादन की तुलना में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है।

(ज) गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य 1993-94 में 34.50 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1994-95 में 39.10 रुपए प्रति क्विंटल कर दिए हैं जिसमें 8.5 प्रतिशत की मूल वसूली की व्यवस्था है और उस स्तर से अधिक प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि पर आनुपातिक प्रीमियम दिए जाने की भी व्यवस्था है। इसके अलावा, सरकार विभिन्न राज्यों में गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत से विकासात्मक कार्यक्रम भी चला रही है।

विवरण

चुनिन्दा राज्यों में चीनी मिलों द्वारा गन्ने के लिए भुगतान किए गए मूल्य

(मूल्य रुपए प्रति क्विंटल में)

राज्य	1991-92	1992-93	1993-94
	अधिकतम न्यूनतम	अधिकतम न्यूनतम	अधिकतम न्यूनतम
आंध्र प्रदेश	31.52–40.59	35.56–48.65	39.37–56.33
गुजरात	27.00–60.00	उ० न०–उ० न०	31.00–50.00
कर्नाटक	30.89–45.00	29.36–50.00	45.00–65.00
तमिल नाडु	31.00–44.40	36.35–55.11	36.35–55.11
उत्तर प्रदेश	45.00–48.00	46.00–49.00	50.00–61.00
महाराष्ट्र	29.00–52.50	31.00–49.65	36.00–61.00

उ०न०=उपलब्ध नहीं।

Univcrsalisation of Primary Education

*255. SHRI SOM PAL: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an intensive study has been conducted recently in certain States regarding universalisation of primary education in the country;

tb) if «o, what are the details thereof: and

hat changes are proposed to be naa 'e by Government in the primary education system as a result thereof?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH) : (a) to (c) As part of the preparatory exercises for District Primary Education Programme (DPEP), Br<feline Studies were conducted in 46 districts spread over 8 States.

Studies reveal that the position of learning achievement is quite low in several of these districts. The findings of the study have helped to define be tt relevant strategies for interventions under D'stnct Primary Education Pro^n'mme like integrated pedagofty, teacher training ■--Virnliim development ba^ed or- miiltigrade teaching requirements, under the programme.

स्व-वित्त योजना–7 के अंतर्गत मकान

*256. **श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या शहरी विकास मंत्री 9 दिसम्बर, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 613 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्व-वित्त योजना-7 के अन्तर्गत कौन-कौन से क्षेत्रों के लिए और कितने मकानों के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए थे ;

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को दुबारा बढ़ाया गया था ; यदि हाँ, तो किस तारीख तक और इसके क्या कारण थे; और

(ग) बढ़ाई गई अवधि के दौरान कितने आवेदन प्राप्त हुए ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी नई स्व-वित्त पोषित आवासीय स्कीम- VII के अन्तर्गत द्वारका और रोहिणी में लगभग 3200 स्व-वित्त पोषित स्कीम फ्लैट (श्रेणी–II) हेतु आवेदन पत्र मांगे थे।